



बड़े आकार के, फल पर निर्भर रहने वाले, टुकन, इसकी लैंगड ग्वान, जेकस और कर्ल क्रैस्टेड जे तथा अन्य पक्षी जमीन पर बीज बिखेर कर जंगलों को नया जीवन देने में सहयोग करते हैं। ऐसा करके वो जंगल की कार्बन स्टोरेज की क्षमता 38 प्रतिशत तक बढ़ा सकते हैं, बर्शात वनों की कटाई ना हो। जर्नल नेचर क्लाइमेट चेन्ज में प्रकाशित यह अध्ययन स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नॉलॉजी ज्यूरिख की क्रोथर लैंड के वैज्ञानिकों ने किया है। शोध की सहलेखक डैनियल लील रामोस, जो सार्गो पाओलो युनिवर्सिटी की इकोलॉजिस्ट हैं, ने कहा "वनों की कटाई में कमी और वनों का पुनः विकास, वातावरण से कार्बन को कम करने और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। डैनियल कहती हैं कि एम्पेजोन और एटलांटिक के जंगलों में पौधों की अधिकांश प्रजातियाँ अपने बीजों को दूर तक बिखरने (प्रकीर्णन) के लिए जीव जंतुओं पर निर्भर रहती हैं। बीजों को दूर तक ले जाकर जमीन पर बिखरने में पक्षी भी अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा, हमारे शोध का उद्देश्य नैचुरल रीजनरेशन और कार्बन सोखने की क्षमता बढ़ाने में फल खाने वाले पक्षियों के योगदान की गणना करना था। शोधकर्ताओं ने हालिया वर्षों में एटलांटिक फॉरेस्ट में एकत्रित डेटा का विश्लेषण किया। शोध के अनुसार फल खाने वाले सभी पक्षी वनों को पुनः विकसित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन बड़े पक्षियों में, जो बड़े फल खा सकते हैं, अंतर यह है कि इनके द्वारा बिखरे गए बीजों से बड़े पेड़ बनते हैं। रामोस ने कहा, बड़े वृक्षों में कार्बन सोखने की क्षमता ज्यादा होती है। ये वृक्ष देर से बढ़ते हैं पर घने होते हैं। तथापि, शोध कहते हैं कि बंजर वनों में पक्षियों का मुवर्मेद कम होता है, जिससे बीजों के फैलने व कार्बन अवशोषण की क्षमता कम हो जाती है। इस तरह के क्षेत्र में जंगल विखंडित होते हैं और फॉरेस्ट पैच एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। ऐसे में पक्षियों को एक से दूसरे पैच जाने के लिए लम्बी उड़ान भरनी पड़ती है, जिससे पक्षियों को परभक्षियों व मौसम के दुष्प्रभाव से सामना करना पड़ता है। मुख्य शोध लेखक कैरोलाइना ने कहा, पक्षी बीजों को अच्छी तरह से बिखरे इसके लिए जरूरी है कि कम से कम 40 प्रतिशत फॉरेस्ट कवर कायम रखा जाए तथा जंगल के दो खंडों की दूरी 133 मीटर से अधिक ना हो।

## कर्नाटक में कन्नड़ भाषा का मजाक उड़ाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कर्नाटक के राज्योत्सव में यह चेतावनी देते हुए बाहर से आने वालों को कन्नड़ सीखने क सलाह दी

- लक्ष्मण वेंकट कुची -  
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 2 नवम्बर। शुक्रवार को पूरे कर्नाटक में "कन्नड़ गौरव" छाप रहा क्योंकि इस दिन कर्नाटक स्थापना दिवस के रूप में "राज्योत्सव डे" मनाया गया। मुख्यमंत्री ने भाषा विवाद को और हवा देते हुए चेतावनी दी कि कर्नाटक में जो भी कन्नड़ भाषा का मजाक उड़ाते पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।

मुख्यमंत्री की चेतावनी ऐसे समय में आई है जब बैंगलूर शहर और सोशल मीडिया पर ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिनमें कन्नड़ भाषा व इसे बोलने वालों पर घृणास्पद टिप्पणियों की बाढ़ आई हुई है। उनमें से मुन्नू पर बंगलूर पुलिस ने संज्ञान लिया है और कथित आरोपी

यही नहीं, मुख्यमंत्री ने यह संकेत भी दिया कि अगर किसी ने कर्नाटक में कन्नड़ भाषा का मजाक उड़ाया तो उस पर 'राजद्रोह' का आरोप भी लगाया जा सकता है।

कर्नाटक स्थापना दिवस पर आयोजित 'राज्योत्सव' में मुख्यमंत्री पूरी तरह से कन्नड़ समर्थक के रूप में नजर आए और कहा कि कर्नाटक में बनी हरकत वस्तु पर कन्नड़ भाषा में लेबल लगाया जाना चाहिए।

हाल ही में बैंगलूर में और सोशल मीडिया पर कन्नड़ भाषा व कन्नड़ बोलने वालों को अपमानित करने की घटनाओं में वृद्धि हुई है तथा पुलिस आरोपियों को ट्रैक कर कार्यवाही कर रही है।

को ट्रैक कर उसका माफिनामा भी रिपोर्ट किया। असल में कन्नड़ लोग इस बात से नाराज है कि यहां रहने वाले बाहरी लोग

बैसिक कन्नड़ भी नहीं सीखना चाहते हैं। यही नहीं बाहरी लोग स्थानीय लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं क्योंकि

वे हिंदी नहीं बोलते हैं जो कि राष्ट्रीय भाषा है।

इस बारे में लगता है जानकारी का अभाव है। भारतीय संविधान व अंग्रेजी के साथ हिंदी को सरकारी भाषा का दर्जा दिया है और राज्य हिंदी व अंग्रेजी में से एक भाषा चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके अलावा यह प्रावधान है कि स्थानीय भाषा राज्य की भाषा मानी जाएगी। लेकिन हाल ही में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। जिनमें बाहरी लोग न केवल कन्नड़ सीखने से मना कर रहे हैं बल्कि हिंसक हो रहे हैं। उनका कहना है कि स्थानीय लोगों को हिन्दी बोलनी चाहिए।

उनकी धारणा है कि हिंदी सभी जगह बोली जाती है अब कर्नाटक में, कांग्रेस ने बड़ी चतुराई के साथ भाषा के (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## पांच नवम्बर को चुनाव होना है, हैरिस मात्र एक प्रतिशत वोट से आगे हैं

अमेरिका के बारे में प्रचलित है, दस प्रतिशत वोट अंतिम दो दिनों में अपना मानस बदल लेते हैं

- सुकुमार साह -  
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -  
नई दिल्ली, 2 नवम्बर। ताजा फोर्ब्स पोल बता रहा है कि अमेरिका में राष्ट्रपति पद की डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस को रिपब्लिकन प्रत्याशी डॉनल्ड ट्रम्प पर मामूली सी एक पॉइन्ट की बढ़त मिल रही है। इससे यह संकेत मिल रहा है कि अमेरिका के चुनावों का नतीजा अनिश्चित है तथा अंतिम परिणामों का निर्णय आखिरी क्षणों में ही होगा।

फोर्ब्स पोल के अनुसार 5 नवम्बर को होने वाले चुनाव से मात्र चन्द्र रोज पहले सांख्यिकीय रूप से मुकाबला बराबर का है तथा ऐसी संभावना है कि दस में से एक मतदाता आखिरी क्षण में अपना मानस बदल सकता है।

पिछले सप्ताह के फोर्ब्स सर्वे के अनुसार, ट्रम्प 49 प्रतिशत तथा हैरिस 48 प्रतिशत पर थीं। इसके अलावा, पोल बताता है कि हैरिस युद्धक्षेत्र वने 7 महत्वपूर्ण राज्यों में 48 प्रतिशत की तुलना में, 49 प्रतिशत से आगे हैं। ये सात राज्य चुनाव परिणाम तय कर सकते हैं। करीब 16 प्रतिशत संभावित मतदाता तथा 10 प्रतिशत रजिस्टर्ड वोटर अभी तक अनिश्चय की स्थिति में हैं, जिसका अर्थ यह निकलता है कि ये वोटर किसी भी पक्ष में शिफ्ट हो सकते हैं।

फोर्ब्स पोल उसी दिन जारी हुआ

इसलिए परिणामों के बारे में कुछ दावे से कहना सम्भव नहीं लग रहा है और चुनाव नतीजों में भारी उलटफेर हो सकता है। नवीनतम फोर्ब्स पोल के अनुसार हैरिस को 49 प्रतिशत और ट्रम्प को 48 प्रतिशत वोटर्स का समर्थन प्राप्त है।

इसी बीच हैरिस की आर्थिक योजना ने बड़ी संख्या में आर्थिक विशेषज्ञों, उद्योगपतियों आदि का ध्यान खींचा है।

विशेषज्ञों का मत है, हैरिस के प्लान में नवाचार और बुनियादी ढांचे पर फोकस किया गया है और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था के लिए इन क्षेत्रों में निवेश महत्वपूर्ण है।

विशेषज्ञों का मत है कि हैरिस का आर्थिक प्लान ठोस है और अमेरिकन अर्थव्यवस्था के लिए बेहद फायदेमंद है। इससे दुनियाभर में अमेरिकन सामान व सेवाओं की मांग बढ़ेगी।

था, जिस दिन ट्रम्प ने, हैरिस के साथ इन्टरव्यू के संबंध में, सी.बी.एस. न्यूज के खिलाफ 10 अरब डॉलर का केस दायर किया था। अक्टूबर के आरम्भ में यह इंटरव्यू "60 मिनट" टेलीकास्ट हुआ था।

ट्रम्प ने इस इंटरव्यू को भ्रामक बताया है। मुकदमे में कहा गया है कि सी.बी.एस. द्वारा टेलीकास्ट किये गये इंटरव्यू में इजराइल-हमास संघर्ष के बारे में हैरिस दो भ्रम बयान हैं।

ट्रम्प ने अपने प्रचार के दौरान इस मुद्दे को लेकर सी.बी.एस. की

आलोचना की है तथा धमकी दी है कि अगर उनकी जीत होती है तो उसका नेटवर्क लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा।

सी.बी.एस. ने कहा है कि ट्रम्प ने अपना 60 मिनट का निर्धारित इंटरव्यू निरस्त कर दिया था। सी.बी.एस. न्यूज के प्रवक्ता ने ट्रम्प के दावों को गलत बताया है तथा दृढ़तापूर्वक कहा है कि मुकदमा मैरिट-विहीन है तथा सी.बी.एस. इसके खिलाफ जोरदार बचाव प्रस्तुत करेगा।

इस बीच, हैरिस की आर्थिक योजना ने बड़ी संख्या में विशेषज्ञों, जिसमें अर्थशास्त्री, अग्रणी व्यवसायी

तथा नीति-विश्लेषक शामिल हैं, का ध्यान अपनी ओर खींचा है। कई अर्थशास्त्रियों ने हैरिस की उन व्यापक आर्थिक रणनीतियों के महत्व पर जोर दिया है, जो असमानता, श्रम शक्ति विकास तथा टिकाऊ ग्रोथ को मद्देनजर रखती है।

विभिन्न उद्योगों के एजीक्यूटिव यह मानते हैं कि हैरिस का इस आर्थिक योजना का फोकस नवाचार तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर पर है। प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा स्वच्छ ऊर्जा में निवेश किया जाना बहुत महत्वपूर्ण है।

नीति-विश्लेषक प्रायः इस प्रकार की आर्थिक योजनाओं बड़े निहितार्थों पर फोकस करते हैं। "विशाल आर्थिक रणनीति वैश्विक स्थिरता का प्राण-तत्व होती है तथा उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए नज़ीर प्रस्तुत करते हैं।"

बड़ी और भारी-भरकम अमेरिकन आर्थिक योजना अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिकन अर्थव्यवस्था वैश्विक बाजारों को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। मजबूत अमेरिकन अर्थव्यवस्था विश्व स्तर पर, जिसमें भारत जैसे देश शामिल हैं, को प्रभावित करती है। अमेरिका की बड़ी हुई आर्थिक ग्रोथ भारतीय व्यवसायों के लिए उभरत व्यापारिक संबंधों की ओर ले जाती है तथा उनके लिए बेहतर अवसर (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## लश्कर का टॉप कमांडर मारा गया

श्रीनगर, 02 नवंबर। जम्मू कश्मीर में अल-अलाना मुठभेड़ों में तीन आतंकवादी मारे गये और चार सुरक्षाकर्मी घायल हो गये।

आधिकारिक प्रवक्ता ने शनिवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि अनंतनाग जिले में मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए मारा गया विदेशी आतंकवादी उस्मान भाई पाकिस्तानी लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर है। जबरक श्रीनगर में एक

श्रीनगर के खनयार क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में लश्कर ए-तैयबा का कमांडर उस्मान भाई पाकिस्तानी मारा गया है।

संदिग्ध विदेशी आतंकवादी मारा गया। आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने पुराने श्रीनगर के खनयार इलाके में शुक्रवार की रात संयुक्त घेराबंदी और तलाश अभियान आज शुरू किया। इसी दौरान वहां मौजूद (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## अडानी का नया प्रेम भूटान

अडानी ग्रुप भूटान में निवेश की नई संभावनाएं तलाश रहे हैं

-जाल खंबाता-  
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-  
नई दिल्ली, 2 नवम्बर। गौतम अडानी भूटान के गेलफू माइन्डफुलनेस सिटी में निवेश के नए अवसर तलाश रहे हैं। यह एक नया प्रोजेक्ट है, जिसका लक्ष्य भूटान के दक्षिणी क्षेत्र को एक इकोनॉमिक हब बनाना है। गेलफू गवर्नर लोटास शेरिंग ने ब्लूमबर्ग को बताया कि भूटान अडानी ग्रुप के साथ भारतीय सीमा के करीब स्थित 1000 वर्ग किलोमीटर की महत्वाकांक्षी टाउनशिप में सोलर प्लांट और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स बनाने की योजना है।

भूटान की निवेश सम्बन्धी योजनाओं से स्पष्ट है भारत का भूटान के साथ पुराना रिश्ता है और भारत भूटान की ग्रोथ को क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का जवाब मानता है। अडानी ग्रुप इजराइल, कोरिया, श्रीलंका, बांग्लादेश व वियतनाम के ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट चला रहा है।

भारत की सीमा पर स्थित भूटान के गेलफू सिटी के गवर्नर लोटास शेरिंग ने ब्लूमबर्ग को बताया कि गेलफू को इकोनॉमिक हब बनाने के लिए अडानी ग्रुप के साथ वार्ता चल रही है।

अडानी गेलफू में सोलर एवं हायड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट्स लगाने की दिशा में काम कर रहे हैं।

भूटान में अनिल अम्बानी की भी दिलचस्पी बताई जाती है वे भी सोलर प्लांट्स एवं हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट्स के क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं।

गवर्नर शेरिंग, जो 2023 तक भूटान के प्रधानमंत्री थे, ने बताया कि गेलफू क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा के लिए सैकड़ों जगह चिन्हित की गई हैं। इस प्रोजेक्ट में सड़कें, पुल व अन्य सुविधाओं का निर्माण भी शामिल है, ताकि एशिया के अन्य निवेशकों को आकर्षित किया जा सके। एनर्जी प्रोजेक्ट्स के अलावा

इन्टरनेशनल एयर पोर्ट एवं ड्राय पोर्ट के निर्माण के लिए भी अडानी ग्रुप से चर्चा चल रही है। चर्चा है कि अडानी को इसमें दिलचस्पी है। एयरपोर्ट प्रोजेक्ट अभी योजना के स्तर पर है इससे गेलफू की एयरस्ट्रिप अपग्रेड हो सकेगी। अभी यह सिर्फ एक मात्र टर्बोप्रॉप एयरक्राफ्ट के लिए ही अनुकूल है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## अपनी "ऑबिचुअरी" लिखने के बाद स्वर्गवासी हुए देबराय

-जाल खंबाता-  
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-  
नई दिल्ली, 3 नवम्बर। प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक काउन्सिल के चेयरमैन, बिबेक देबराय का 69 वर्ष की उम्र में 1 नवम्बर को निधन हो गया। उन्होंने ऑल इण्डिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मैडिकल साइन्सेज में अंतिम सांस ली, वे एक महीने से बीमार थे। एक प्रोफाउण्ड स्लम्पकार के रूप में मृत्यु से

अपनी मृत्यु से 4 दिन पहले देबराय ने अपनी 'ऑबिचुअरी' इण्डियन एक्सप्रेस को भेजी थी।

चार दिन पहले, 28 अक्टूबर को उन्होंने स्वयं अपनी ऑबिचुअरी (मृत्युलेख) लिखकर इण्डियन एक्सप्रेस को भेज दी थी, जिसे इस अखबार ने उनकी मृत्यु के दिन प्रकाशित किया।

उनका अंतिम संस्कार 3 नवम्बर को 3 बजे दोपहर को लोधी रोड श्मशान में होगा, अमेरिका से उनके पुत्रों के आने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## जैव विविधता नष्ट करने में भारत विश्व में पांचवे नम्बर पर

नेचर कंज़र्वेशन इंडैक्स (2024) के अनुसार 180 देशों की लिस्ट में भारत 176 वें नम्बर पर है

- डॉ. सतीश मिश्रा -  
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 2 नवंबर। नेचर कंज़र्वेशन इंडैक्स (एन.सी.आई.) 2024 के नवीनतम निष्कर्षों में भारत को जैवविविधता के नुकसान और संरक्षण प्रयासों की कमी के मामले में सबसे खराब पांच देशों की सूची में रखा है।

जिन 180 देशों का अध्ययन किया गया उनमें भारत का स्कोर 45.5 और रैंक 176 है। केवल किरिबाती, तुर्की, इराक और माइक्रोनेशिया देशों का स्कोर भारत से खराब है।

अक्टूबर में लॉन्च किया गया प्रथम एन.सी.आई., भूमि प्रबंधन जैव विविधता के लिए खतरों, क्षमता और शासन और पवित्र्य के रुझानों, इन चार मार्कों का उपयोग करके संरक्षण प्रयासों का मूल्यांकन करती है।

जबकि, विश्व रिपोर्ट चिंताजनक है, लेकिन मोदी सरकार की प्रतिक्रिया हमेशा जैसी ही होगी। जो इसकी पूर्ण रूप में खारिज करके ऐसे

किरीबाती, तुर्की, इराक और माइक्रोनेशिया देशों का प्रदर्शन भारत से खराब है। इन्डैक्स तैयार करने में लैण्ड मैनेजमेंट, जैव विविधता को खतरा, क्षमता व शासन तथा भावी रूझान जैसे मार्कर्स को ध्यान में रखा गया है। इस लिस्ट में लमजमबर्ग, एस्टोनिया, डैनमार्क, फिनलैंड और यूनाइटेड किंगडम "टॉप फाइव" देश हैं।

वक्तव्य देते कि रिपोर्ट का भारत के प्रति पक्षपातपूर्ण रखा है। इजरायल की, बैन-गुरियन युनिवर्सिटी ऑफ नेगेव में गोल्डमैन सोननफैल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनिबिलिटी एण्ड क्लाइमेट चेंज और गैर लाभकारी वैबसाइट बायो डी.बी. द्वारा विकसित सूचकांक के अनुसार जैव विविधता (बायो डायवर्सिटी) के संरक्षण और सुरक्षा के मामले में शीर्ष पांच देश हैं, लगजमबर्ग, एस्टोनिया, डैनमार्क, फिनलैंड और यूनाइटेड किंगडम। एन.सी.आई. 2024 के साइटेशन में कहा गया है कि, "भारत दुनिया के मैगा-विविध देशों में से एक है, जिसमें दुनिया की लगभग 7-8

प्रतिशत डॉक्यूमेंटेड प्रजातियां, कुल भूमि क्षेत्र के केवल 2.4 प्रतिशत हिस्से में फैली हुई हैं। एन.सी.आई. 2024 का बायोडीबी वेबसाइट पर कहना है, "अभी हाल ही में विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला देश बनने जा रहे, भारत में वन्यजीवों तथा उनके आश्रय स्थलों का विविधतापूर्ण फैलाव है। बर्फीले हिमालय से लेकर उष्ण कटिबन्धीय पश्चिमी घाट तथा शुष्क धर मरुस्थल तक, भारत में वन्यजीवों के रक्षक ठिकानों के बहुत ज्यादा विविधता वाले क्षेत्र हैं, जो विविध प्रकार के जीवों को आश्रय देते हैं।

"एशियन हाथी, भारतीय गैंडा तथा बगाली

चीते जैसे प्रसिद्ध जानवरों के साथ ही, भारत विभिन्न प्रकार के पक्षियों, रंगने वाले जीवों तथा समुद्री जीव-जन्तुओं का घर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने-पहचाने 36 बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट्स में से 4 क्षेत्र भारत की सीमा के अंदर हैं-हिमालय, इंडो-बर्मास पश्चिमी घाट तथा सुंडालैंड हैं (जिनमें से 61,375 फीट हैं) तथा 10 बायोज्योग्राफिक क्षेत्रों में 45,500 पौधों की प्रजातियां हैं। एन.सी.आई. वेबसाइट के अनुसार, रिपोर्ट में 180 देशों की बायोडायवर्सिटी के विश्लेषण के लिए 25 इन्डिकेटर्स का विश्लेषण किया गया है। इस जैव-विविधता तथा संरक्षण

(बायोडायवर्सिटी एंड कंज़र्वेशन) अध्ययन के चार प्राथमिक आधार बिन्दु हैं - लैंड मैनेजमेंट, थ्रेट्स टु डायवर्सिटी, कैपेसिटी एंड गवर्नेंस, तथा फ्यूचर ट्रेंड्स।

एन.सी.आई. के अनुसार, सबसे निकट रैंकिंग का अर्थ है कि भारत में इन जीवों के रहने के ठिकाने कम हो रहे हैं, इनकी संख्या कम हो रही है, तथा वाइल्ड लाइफ एवं प्लांट पापुलेशन अपभूतपूर्व गति से कम होती जा रही है। तथा संरक्षण-कानून संतोषजनक नहीं हैं। भारत के पड़ोसी देशों, बांग्लादेश (173), पाकिस्तान (151), श्रीलंका (90), नेपाल (60), भूटान (15) तथा चीन (164) सभी की रैंकिंग भारत से बेहतर है। तुलनात्मक अर्थव्यवस्थाओं-मैक्सिको (42), थायलैंड (80), इंडोनेशिया (122) तथा संयुक्त अरब अमीरात (111) की रैंकिंग भी भारत से बेहतर है। यहाँ कुछ उदाहरण दिये जा रहे हैं। भारत में, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## 'फर्जी क्लेम वालों पर कार्यवाही कर सकती हैं बीमा कम्पनियाँ'

जयपुर, 2 नवंबर। जिले की स्थाई लोक अदालत ने फर्जी व झूठे क्लेम के मामलों को गंभीरता से लेते हुए बीमा कंपनियों को कहा है कि वे ऐसा करने

स्थाई लोक अदालत ने चोला मंडल इंश्योरेंस के खिलाफ क्लेम याचिका को फर्जी मानते हुए खारिज कर दिया तथा बीमा कंपनी को अपराधिक मामला दर्ज करने की अनुमति दी।

वाले व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। कोर्ट ने विपक्षी बीमा कंपनी चोला मंडल एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ 9.16 लाख रुपए की क्लेम (शेष अंतिम पृष्ठ पर)